रेल बजट 2006-07 की विशेषताएं

2005-06 के दौरान निष्पादन की समीक्षा एवं संशोधित अनुमान

- वर्ष 2005-06 के प्रथम नौ माह के दौरान रिकार्ड तोड़ निष्पादन.
- माल लदान एवं राजस्व में क्रमशः 10% एवं 18% से अधिक की वृद्धि दर्ज.
- लदान का लक्ष्य 635 मिलियन टन से बढ़ाकर 668 मिलियन टन एवं माल राजस्व का लक्ष्य 33480 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 36490 करोड़ रुपए किया गया.
- दसवीं योजना के 624 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग एवं 396 मिलियन टन किलोमीटर के लक्ष्यों को एक वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया.
- यात्री आय, अन्य कोचिंग आय एवं विविध आय में क्रमशः 7%, 19% एवं 56% की वृद्धि दर्ज.
- सकल यातायात आय 54600 करोड़ रुपए होने की संभावना जो गत वर्ष से 16 % अधिक.
- साधारण संचालन व्यय में 1200 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी.
- संभावित ऑपरेटिंग रेशियो 86.6%; लीज़ प्रभार संबंधी लेखांकन प्रथा में परिवर्तन के फलस्वरूप ऑपरेटिंग रेशियो 83.7% हो जाएगा.
- वर्ष के अंत में फंड बैलेंस 11280 करोड़ रुपए होने की संभावना.

2006-07

- प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता.
- ऊंची वॉल्यूम क्षमता वाले वैगनों के नए डिज़ाइन का काम जारी और वर्ष 2006-07 में एल्युमिनियम व स्टेनलेस स्टील के वैगन का निर्माण.
- पे-लोड टेयर-वेट रेशियो सुधरकर 3:1 से भी बेहतर और आगे चलकर लगभग 4:1 होगा.
- ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा एवं आईटी का विस्तार.
- पब्लिक पार्टनरशिप एवं पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर भरपूर जोर.
- उपयुक्त रेल परियोजनाएं खुली निविदा द्वारा भी दी जाएंगी.
- निजी पार्टियों को कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति देने संबंधी नीति को व्यापक समर्थन मिला, 14 आवेदकों ने 540 करोड़ रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराया.
- प्राइवेट कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए 31 मार्च, 2006 से पहले अनुमति दे दी जाएगी.
- डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन मार्च, 2006 में शुरू.
- अनुकूल नीतिगत पहल द्वारा मजबूत वैगन लीज़िंग मार्केट का विकास.

माल व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए कदम

- वैगन की लदान क्षमता बढ़ाकर एवं अन्य कदमों द्वारा माल परिवहन की प्रति इकाई लागत में कमी

- प्रति वैगन 4 से 8 टन लोडिंग बढ़ाने से लोडिंग क्षमता में 100 मिलियन टन का इज़ाफा जिससे 5000 करोड़ रुपए की राजस्व वृद्धि.
- 25 टन एक्सल लोड की गाड़ी दो मार्गों पर चलेगी- भारतीय उपमहाद्वीप में यह पहली बार.
- सीसी रेक के ब्रेक पॉवर सर्टिफिकेट की वैधता 6000 किमी से बढ़कर 7500 किमी.
- यातायात वरीयता अनुसूची में संशोधन, 800 किमी से अधिक दूरी वाले फ्रेट को अपनी श्रेणी के अंतर्गत वरीयता.
- वैगन निर्माण में लगभग 25% की वृद्धि.
- विद्युत व डीज़ल रेलइंजनों के उत्पादन में क्रमश: 17% एवं 5% की वृद्धि.

यात्री व्यवसाय के घाटे में कमी

- यात्री व्यवसाय के लिए भी 'व्यापार बढ़ाओ, प्रति इकाई लागत घटाओ' की रणनीति.
- यात्री गाड़ियों के कोचों की संख्या एवं आक्यूपेंसी बढ़ाकर, यात्रा समय में कटौतीकर तथा कैटरिंग एवं पार्सल व्यवसाय में हो रहे घाटे को कम कर कोचिंग सेवाओं पर हो रहे घाटे में अगले वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए एवं 3 वर्षों में 50% की कमी लाने का निश्चय.
- आल इंडिया टाईम-टेबल को कंप्यूटराइज्ड सिमुलेशन तकनीक की सहायता से नए सिरे से बनाया जाएगा.
- 200 से अधिक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां सुपर फास्ट बनेंगी.
- अधिकांश शताब्दी, राजधानी व कई मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के यात्रा समय में कमी.
- 190 लोकप्रिय यात्री गाड़ियां 23-24 कोच की होंगी, इससे प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय.
- 60 करोड़ रुपए की लागत से 200 स्टेशनों के प्लेटफार्म का विस्तार.
- सभी राजधानी व मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में निम्न श्रेणी के यात्रियों का बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के उच्च श्रेणी में अपग्रेडेशन.

पार्सल एवं कैटरिंग व्यवसाय के घाटे में कमी

- पैंट्री कारो एवं बड़े स्टेशनों पर कैटरिंग इकाइयों की खुली निविदा द्वारा लीज़िंग जारी.
- पार्सल क्षमता के उपयोग में सुधार.
- ब्रेक वैन एवं पार्सल वैन की लीज़िंग पॉलिसी का उदारीकरण.
- खुली निविदा आमंत्रित, अपर्याप्त रिस्पांस की स्थिति में निर्धारित रिज़र्व प्राइस में चरणबद्ध कटौती.
- 5 मिनट या अधिक हॉल्ट वाले सभी स्टेशनों पर पार्सल लोडिंग/अनलोडिंग एवं लीज़ होल्डर्स को स्वयं लोडिंग मैनीफेस्ट बनाने की अनुमति.
- सहायक गार्ड डिब्बे की लीज़ कोरियर कंपनी के अलावा ब्रेक वैन एवं पार्सल वैन के लीज़ होल्डर्स को भी उपलब्ध.
- ब्रेक वैन में सामान बुक करने के लिए 150 किलोग्राम की सीमा हटी.
- साधारण यात्री गाड़ियों के ब्रेक वैन के लगेज वाले हिस्से को द्वितीय श्रेणी डिब्बे में बदला जाएगा.

वर्ष 2006 मुस्कान के साथ यात्री सेवा का वर्ष घोषित

टिकट काउंटर की लंबी लाइन को छोटा करने की नीति

- ई-टिकट पर लिए जाने वाले शुल्क में कमी.
- आई-टिकट एवं ई-टिकट रेल ट्रैवल सर्विस एजेंट के माध्यम से भी खरीदे जा सकते हैं.
- 800 नए यूटीएस केन्द्र खोले जाएंगे.
- मुंबई महानगर के उपनगरीय खंडों में 200 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी.
- 'जनसाधारण टिकट बुकिंग योजना' के तहत बेरोजगार युवकों को रोड-साइड स्टेशनों पर टिकट बेचने की एजेंसी दी जाएगी.
- ग्रामीण टिकट बुकिंग सेवा के तहत रोड-साइड स्टेशनों पर बेरोजगार युवकों को टिकट बेचने की एजेंसी दी जाएगी.

यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना

- ए और बी श्रेणी के सभी स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा.
- स्टेशन भवनों को अधिक सुंदर, सुविधाजनक एवं आधुनिक बनाने के लिए प्रत्येक मंडल में आर्किटेक्ट की मदद ली जाएगी.
- प्रमुख स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं जैसे एटीएम, साइबर कैफे आदि उपलब्ध कराई जाएंगी.
- नई व्यावसायिक विज्ञापन नीति के अंतर्गत खुली निविदा द्वारा पूरे डिवीज़न के लिए लीज़ एक ही एजेंसी को देने की पायलट योजना.
- रिटायरिंग रूम, वेटिंग हॉल, स्टेशन भवन, शौचालय आदि को सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना द्वारा अपग्रेड करने की पायलट योजना कुछ स्टेशनों पर क्रियान्वित, इसे और आगे बढ़ाया जाएगा.

यात्री गाड़ियों में आधुनिक सुविधाएं

- नई तकनीक से बने एलएचबी डिज़ाइन के यात्री डिब्बे पटना, सियालदह राजधानी में भी लगाए जाएंगे.
- 4 लोकप्रिय गाड़ियों के डिब्बों में विश्व स्तर की सुविधा एवं अन्तर्सज्जा.
- कैटरिंग निगम द्वारा गाड़ियों में सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए खुली निविदा द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे.
- ये सेवाएं ऐसी मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों में भी उपलब्ध कराई जाएंगी जिनमें पैंट्रीकार नहीं है.

रेल संरक्षा

- गतायु ट्रैक, पुल एवं ए, बी, सी रूट पर अवस्थित सभी स्टेशनों के ट्रैक सर्किटिंग का कार्य मार्च, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा.
- विशेष रेल संरक्षा निधि के बचे हुए कार्यों को मार्च, 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा.

- वर्ष 2001 के बाद ओवर-एज हो रही परिसंपत्तियों का रिनीवल संबंधी कार्य संबंधित वर्ष में ही स्वीकृत कर निष्पादित किया जा रहा है.
- वर्ष 2001 की तुलना में परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या 473 से घटकर वर्ष 2004-05 में 234 रह गई है.

कर्मचारी कल्याण

- अगले वर्ष के लिए कर्मचारी कल्याण निधि हेतु अंशदान में लगभग नौगुना वृद्धि.
- 100 सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण होगा.
- रनिंग स्टाफ को मुख्यालय से दूर रहने पर कार्य-अवधि के दौरान मामूली दरों पर भोजन की व्यवस्था.
- सभी गैंगमैनों/कीमैनों को उन्नत किस्मों के जूते-मोजे, दस्ताने तथा गर्मी एवं सर्दी के यूनिफार्म व आवश्यक उपकरण मिलेंगे.

चिकित्सा सुविधाओं में सुधार

- पटना में कॉर्डियोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी के नए सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल का निर्माण.
- आगरा, रायपुर एवं नांदेड़ के लिए नए डिवीज़नल हॉस्पिटल.
- आईसीएफ, पेराम्बूर-नए चिकित्सालय भवन के फेज़-I को स्वीकृति.

विशेष भर्ती अभियान एवं अधिकतम आयु-सीमा में छूट का अवधि विस्तार

- चालू वर्ष के दौरान 6000 से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति की रिक्तियां भरी गईं.
- अगले वर्ष ओबीसी रिक्तियों के बैकलॉग की भर्ती हेतु विशेष अभियान.
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु-सीमा में मिल रही छूट का 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार (3 फरवरी, 2006 से).

रियायतें

- राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में कृषि एवं डेयरी पालन से संबंधित प्रशिक्षण अथवा बेहतर शिक्षा हेतु यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी में मिल रही 50% की रियायत अब स्लीपर श्रेणी में भी उपलब्ध.
- दुर्घटना अथवा अन्य कारणों से हाथ, पैर आदि कटने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठानों में कृत्रिम अंग लगवाने के लिए यात्रा के दौरान एक सहचर सहित द्वितीय श्रेणी एवं स्लीपर श्रेणी में 50% की रियायत.

यात्री सेवाएं

- भारत व पाकिस्तान के बीच 'थार एक्सप्रेस' का शुभारंभ.
- दिल्ली-आगरा खंड में 150 किमी प्रतिघंटा वाली गाड़ी का शुभारंभ, दिल्ली-कानपुर-लखनऊ मार्ग पर भी चलेगी.

नई गाड़ियां, गाड़ियों का विस्तार एवं फेरों में वृद्धि

- नई गाड़ियां : 55 जोड़े
- गाड़ियों का विस्तार : 37 जोड़े
- फेरों में वृद्धि : 12 जोड़े
- रूट का पुनर्निर्धारण : 2 जोड़े

फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण

- 22000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पश्चिम एवं पूर्वी मार्गों पर कंप्यूटराज्ड कंट्रोल वाले सर्मपित मल्टीमोडल, हाई एक्सल लोड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण.

वर्कशॉप एवं उत्पादन इकाइयां

- निम्न की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी

  ✓ रेल व्हील फैक्टरी, छपरा
  ✓ इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नै
  ✓ समस्तीपुर वर्कशॉप

- सोनपुर में एक डीएमयू शेड तथा एक वैगन ओवरहॉलिंग वर्कशॉप की स्थापना.
- आरसीएफ, कपूरथला को पूर्ण स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम बनाने के लिए विचार.

निवेश रणनीति

- हाई-डेंसिटी नेटवर्क पर रूट-वार थ्रूपुट सवंर्धन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता.
- सभी बाकी थ्रूपुट संवर्धन कार्य अगले तीन वर्षों में पूरे होंगे.

वार्षिक योजना 2006-07

- 23475 करोड़ रुपए वाली अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना जिसमें शामिल है

  ✓ 7511 करोड़ रुपए का सामान्य राजकोष से समर्थन
  ✓ 10794 करोड़ रुपए के आंतरिक संसाधन
  ✓ 5170 करोड़ रुपए के गैर बजटीय संसाधन (4170 करोड़ रुपए आईआरएफसी द्वारा बाजार से ऋण द्वारा, 500 करोड़ रुपए आरवीएनएल के माध्यम से एवं बाकी 500 करोड़ रुपए वैगन निवेश योजना द्वारा)

- 2240 करोड़ रुपए का कुल एसआरएसएफ परिव्यय-1365 करोड़ रुपए सामान्य राजकोष से एवं 875 करोड़ रुपए आंतरिक संसाधनों से.
- सड़क संबंधी संरक्षा कार्यों पर 711 करोड़ रुपए का परिव्यय.
- वार्षिक योजना में थ्रूपुट संवर्धन कार्यों, संरक्षा, नेटवर्क के विकास एवं विस्तार संबंधी कार्यों को शीघ्र पुरा करने पर बल.
- संरक्षा संबंधी योजना शीर्षों में परिव्यय है- रेलपथ नवीकरण के लिए 2922 करोड़ रुपए, पुलों के लिए 590 करोड़ रुपए, सिगनल एवं दूरसंचार के लिए 1518 करोड़ रुपए, आरओबी-आरयूबी निर्माण के लिए 436 करोड़ रुपए एवं मानव रहित समपारों को मानवयुक्त करने के लिए 275 करोड़ रुपए.
- राष्ट्रीय परियोजनाएं- वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा कार्य की प्रगति के आधार पर निधि की व्यवस्था. 2092 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है.

परियोजनाएं

- 2006-07 के लक्ष्यों में शामिल हैं: 550 किमी से अधिक की नई लाइनें, 1100 से अधिक के आमान परिवर्तन एवं 435 किमी का दोहरीकरण.
- सर्वेक्षण : 23 नई लाइनें, एक आमान परिवर्तन एवं 8 दोहरीकरण.

बजट अनुमान 2006-07

- माल लदान का लक्ष्य 726 मिलियन टन एवं माल निष्पादन का लक्ष्य 479 बीटीकेएम होगा.
- माल, यात्री, अन्य कोचिंग तथा विविध आय क्रमशः 40320 करोड़ रुपए, 16800 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए एवं 1308 करोड़ रुपए होंगी.
- सकल यातायात प्राप्तियां 59978 करोड़ रुपए होंगी.
- साधारण संचालन व्यय 38300 करोड़ रुपए होंगे.
- पेंशन निधि एवं मूल्य ह्रास आरक्षित निधि को विनियोग क्रमशः 7790 करोड़ रुपए एवं 4307 करोड़ रुपए होगा.
- लाभांश पूर्व आंतरिक संसाधन 14293 करोड़ रुपए होंगे.
- 2006-07 में ऑपरेटिंग रेशियो 84.3% होने की संभावना.

मालभाड़ा एवं यात्री किराए संबंधी प्रस्ताव

मालभाड़ा सेवाएं

- मालभाड़ा दरों में कोई सामान्य वृद्धि नहीं.
- मालभाड़ा दरों का युक्तिकरण जारी.
- वस्तुओं के समूहों की संख्या 80 से घटकर 28 होगी.
- उच्चतम श्रेणी घटकर 220 हुई, डीज़ल एवं पेट्रोल के भाड़े 8% कम होंगे.

- अगले तीन वर्षों में उच्चतम श्रेणी 200 के अंदर लाई जाएगी और उच्चतम श्रेणी की दरें न्यूनतम श्रेणी की दरों की तुलना में दोगुने से कम होंगी (कुछ हल्की वस्तुओं को छोड़कर).
- हल्की वस्तुओं के लिए लागू वर्तमान दरों 90डब्ल्यू1, 90डब्ल्यू2 एवं 90डब्ल्यू3 को नई श्रेणियों एलआर1, एलआर2, एलआर3, एलआर4 एवं एलआर5 से बदला गया जो श्रेणी 100 के सापेक्ष क्रमश 90%, 80%, 70%, 60% एवं 50% होंगी.

घोषित स्कीमें

- चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी यात्री परिवहन के लिए भी लागू. यह पॉलिसी पीक एवं नॉन-पीक सीजन, प्रीमियम एवं नॉन-प्रीमियम सेवा और व्यस्त एवं गैर-व्यस्त मार्गों के लिए अपनाई जाएगी.
- नॉन-पीक सीजन इंक्रीमेंटल फ्रेट डिस्काउंट स्कीम की घोषणा.
- एम्पटी फ्लो डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल फ्रेट पर कुछ शर्तों के साथ नॉन-पीक सीजन एवं पीक सीजन में क्रमश: 30% एवं 20% की छूट.
- सीमेंट एवं आयरन व स्टील के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए लॉयल्टी डिस्काउंट स्कीम की घोषणा.
- नए ग्राहकों तथा नए माल यातायात को आकर्षित करने के लिए लॉग टर्म फ्रेट डिस्काउंट स्कीम की घोषणा.
- मिनी रेक एवं टू-प्वाइंट रेक स्कीम पीक एवं नॉन-पीक दोनों सीजनों में उपलब्ध होगी.
- 700 किलोमीटर से अधिक के फ्रेट के लिए नई फ्रेट फॉरवर्डर स्कीम.

यात्री सेवाएं

- यात्री किराए में कोई भी वृद्धि नहीं.
- यात्री किराया संरचना इस प्रकार युक्तिकृत की जाएगी कि एसी प्रथम एवं एसी द्वितीय श्रेणी का किराया साधारण श्रेणी के किराए से क्रमशः 11.5 तथा 6.5 गुना होगा. एसी प्रथम एवं एसी द्वितीय श्रेणी के किराए क्रमशः 18% एवं 10% कम होंगे.
- पूरी तरह वातानुकूलित **गरीब रथ** पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर प्रारंभ में 4 जोड़ी सेवाओं के साथ चलेंगे- किराया एसी तृतीय श्रेणी के वर्तमान किराए से करीब 25% कम होगा.
- मासिक सीजन टिकटों के नवीकरण की अवधि तीन दिन से बढ़ाकर 10 दिन की गई और एमएसटी तथा क्यूएसटी के लिए वर्तमान में लिए जाने वाले सुपर फास्ट चार्ज एक चौथाई होंगे.
- मिलिट्री टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया सरलीकृत एवं युक्तिसंगत बनाई जाएगी.

******